Title: Need to review Public Distribution System with a view to check corruption and blackmarketting. -laid.

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा): अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रव्यापी जन वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के द्वारा रियायती मूल्य पर आम जनता को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने की व्यवस्था विगत ५० वर्षों की आजादी में असफल सिद्ध हुई है। कोटा-परमिट एवं नियंत्रण व्यवस्था द्वारा पंचायत स्तर पर स्वच्छन्द भ्रष्टाचार एवं कालाबाजारी बढ़ी है। आवंटित कोटे की सामग्री में से ८० प्रतिशत कालाबाजार में पहुंचा दी जाती है और वहां दुगने-तिगुने दाम पर बिक कर आम जनता का शोषण हो रहा है। केन्द्र सरकार करोड़ों रुपये रियायती मूल्य आपूर्ति कराने के लिए व्यय करती है जिससे लक्षय की पूर्ति नहीं होती। चीनी, गेहूं, किरोसीन तेल आदि आवश्यक वस्तुयें रियायती दर पर मुहैया नहीं हो पाती हैं। शिकायत करने पर आपूर्ति पदाधिकारियों को अनुचित लाभ ही हो जाता है। बराबर बाजार भाव एवं रियायती दरों में भारी अंतर से कालाबाजारी का धंधा भी बरकरार रहता है। अतः जन वितरण प्रणाली को रद्द किया जाये। आवश्यक वस्तुओं का मूल्य निर्धारित किया जाए। व्यवस्था के उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं अन्य कानूनों के तहत कार्रवाई की जाए। इससे व्याप्त भ्रष्टाचार एवं ब्लैक मार्केटिंग समाप्त होगा।